‘अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम’ और ‘सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन’ के विभिन्न मुद्दों का प्रचार करने वाली सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों द्वारा चलाए गए प्रचार पर की गई कार्रवाई नोट

अप्रेल - जून, 2020

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

- पीआईबी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से विज्ञप्तियां/फीचर जारी करता है ।
- इसके विभिन्न क्षेत्रों से इस विषय पर 167 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं।

लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)

➢ *प्रिंट विज्ञापन*

- ब्यूरो अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित विषयों पर अखिल भारतीय आधार पर समय-समय पर विज्ञापन जारी करता रहा है जिनमें उनके लिए उपलब्ध भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों, निधियों, छात्रवृत्तियों आदि की जानकारी दी जाती है।
- बीओसी ने "हुनर हाट" विषय पर तिमाही के दौरान कई समाचार पत्रों में 3 विज्ञापन जारी किए ।

➢ *आउटडोर प्रचार अभियान*

- बीओसी ने तिमाही के दौरान बाह्य प्रचार पर कोई व्यय नहीं किया।

➢ *क्षेत्र प्रचार*

- देश भर में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, लॉकडाउन की मौजूदा शर्तें और इससे संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों के कारण बीओसी के सभी 148 क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो (एफओबी) और 23 प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबी) ने सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक, वॉट्सऐप, टविटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- जागरूकता कार्यक्रमों का विषय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान सहित कोविड-19, भारत सरकार के निर्णय और पहलें शामिल हैं।
- ब्यूरो ने अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों सहित देशभर में जनसमुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग किया।
- तिमाही के दौरान किसी विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। तथापि उपरोक्त जागरूकता कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से चलाया गया।

आकाशवाणी

- सभी आकाशवाणी केंद्रों ने 'अल्पसंख्यक कल्याण' पर उपयुक्त कार्यक्रमों को तैयार करके इस विषय का व्यापक प्रचार किया ।
- विभिन्न स्वरूपों का उपयोग किया गया जिसमें- वार्ता, चर्चा, साक्षात्कार, कम्पीयरिंग, फोन-इन कार्यक्रम, संवादात्मक कार्यक्रम, नाटक, जिंगल आदि शामिल थे।
- कार्यक्रमों में मुख्यतः 15 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न घटकों और सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया।
- तिमाही के दौरान आकाशवाणी केंद्रों द्वारा कुल 801 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन

- देश भर के विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों ने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्यक्रम प्रसारित किए।
- कार्यक्रमों के प्रारूप में चर्चा, फोन-इन, साक्षात्कार, मैग्जीन, लाइव कार्यक्रम, आदि शामिल थे।
- तिमाही के दौरान दूरदर्शन केंद्रों द्वारा कुल 170 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया ।

***

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अप्रैल से जून 2020 तक राज्यवार त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)

सं.	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या	बीओसी द्वारा प्रिंट मीडिया पर खर्च (रु. में)	डीडी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	-	-	6233	-
2	आंध्र प्रदेश	9	-	40,555	-
3	तेलंगाना	-	43	71,646	8
4	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0	-
5	असम	9	13	8736	-
6	बिहार	9	28	2,08,425	3
7	चंडीगढ़	-	-	82,733	5
8	छत्तीसगढ़	3	6	41,769	6
9	मध्य प्रदेश	4	17	3,83,829	25
10	दादरा और नगर हवेली	-	-	12,920	-
11	दमन और दीव	-	-	0	-
12	गुजरात	7	152	1,03,618	-
13	जम्मू और कश्मीर	9	16	1,29,954	-
14	झारखंड	-	8	1,47,757	-
15	कर्नाटक	9	24	1,94,653	2
16	केरल	2	32	62,761	-
17	लक्षद्वीप	-	-	0	-
18	महाराष्ट्र	8	38	6,34,393	-
19	गोवा	-	-	0	2

20	मिजोरम	7	15	0	-
21	मेघालय	-	-	0	9
22	त्रिपुरा	4	-	7643	-
23	नगालैंड	-	-	0	-
24	मणिपुर	-	-	0	-
25	पंजाब	16	23	1,10,421	91
26	हिमांचल प्रदेश	19	10	16,934	4
27	हरियाणा	-	13	1,11,837	3
28	दिल्ली	9	137	9,99,996	-
29	ओडिशा	-	27	36,680	4
30	पुडुचेरी	-	-	0	-
31	राजस्थान	18	20	4,30,849	3
32	तमिलनाडु	-	16	1,85,458	-
33	उत्तराखंड	16	27	1,06,398	-
34	उत्तर प्रदेश	-	14	9,38,857	-
35	पश्चिम बंगाल	-	29	80,458	5
36	सिक्किम	9	93	8432	-

***